

‘इण्डो- यूएस ट्रेड डील पर चार-पांच दिन में दोनों देश संयुक्त बयान देंगे’

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि संयुक्त वक्तव्य के बाद वाइट हाउस के एज़ीक्युटिव आदेश से यूएस टैरिफ घटकर 18 प्रतिशत रह जाएगा

-डॉ. सतीश मिश्रा-

—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 05 फरवरी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि अमेरिका-भारत व्यापार समझौते का पहला चरण लगभग तैयार है और दोनों देश चार-पांच दिनों में संयुक्त बयान जारी करेंगे। सोमवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प द्वारा दृढ़ सोशल पर की गई घोषणा के बाद दिल्ली और वाशिंगटन के बीच समझौते की पहली जानकारी सामने आने लगी है। गोयल ने कहा कि संयुक्त बयान के बाद वाइट हाउस के कार्यकारी आदेश के जरिए अमेरिकी टैरिफ 18 प्रतिशत तक कम हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर करने में 30-45 दिन लगेगे और इसे मार्च में साइन किया जाएगा।

- पीयूष गोयल ने बताया कि औपचारिक एग्रीमेंट होने में 30 से 45 दिन लगेगे और संभवतया मार्च तक एग्रीमेंट हो जाएगा और इस पर मार्च में वर्चुअली साइन किये जाएंगे।
- ट्रंप ने ट्रेड डील की घोषणा सोमवार रात की थी जिसमें यह भी कहा था कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। इसे स्पष्ट करते हुए वाणिज्य विभाग के अफसरों ने बताया कि विमान खरीद के ही ऑर्डर 70-80 अरब डॉलर के होंगे। भारत ईंधन, विमान व चिप्स खरीद पर 300 अरब डॉलर खर्च करेगा।
- वेनेज़ुएला से ईंधन खरीदने के ट्रंप के दावे पर विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा, वेनेज़ुएला हमारा पुराना सहयोगी है, हम उससे तेल खरीदते रहे हैं। पर प्रवक्ता ने रुस से तेल खरीद के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा।

उन्होंने बताया कि संयुक्त समझौते पर वर्चुअल तरीके से हस्ताक्षर किए जाएंगे और संयुक्त बयान के बाद कार्यकारी आदेश के जरिए भारत से आने वाले सामान पर अमेरिकी शुल्क 18 प्रतिशत कर दिया जाएगा। गोयल ने कहा, “हम चाहते हैं कि समझौता जल्दी हो, क्योंकि इसके बाद हमें और रियायतें मिल सकती हैं।” वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा, “मार्च में लीगल एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत अमेरिका के सामान पर शुल्क कम करेगा।” ट्रम्प के इस दावे पर भी कुछ स्पष्टता सामने आई कि भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। व्यापार अधिकारियों ने बताया कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईसाई रीति से हुए विवाहों का रजिस्ट्रेशन करें- हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि ईसाई विवाह अधिनियम के तहत जारी विवाह प्रमाण पत्रों को सिविल रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार नहीं किया जा सकता। यह राज्य का वैधानिक दायित्व है और इसे किसी अधिकारी के विवेकाधीन निर्णय के

- विवाह पंजीकरण नहीं होने से ईसाई दंपतियों को पासपोर्ट, वीज़ा सहित अन्य सरकारी सेवाओं के लिये कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

अधीन नहीं रखा जा सकता। जस्टिस पीएस भाटी और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश सिरो-मालाबार रोमन कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट ईचार्ज फादर पॉल पी की ओर से दायर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

व्हीलचेयर पर संसद पहुंचे थरुर

—जाल खंभाता—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 5 फरवरी। संसद के मकर द्वार से व्हीलचेयर से गुजरते हुए, शशि थरुर ने कहा कि वह संसद में अपने कर्तव्यों और केरल में अपने चुनावी कार्य को जारी रखेंगे। ज्ञातव्य है कि बुधवार को थरुर संसद भवन में गिर गए इस कारण उनके पैर में एक हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है। पत्रकारों से बात करते हुए, तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस के सांसद थरुर ने कहा कि उनका पैर कास्ट में रहेगा और ठीक होने में कम से कम 4-6 सप्ताह लगेगे। थरुर ने कहा, “मैं

- कांग्रेस के सांसद शशि थरुर बुधवार को संसद की सीढ़ियों से लड़खड़ाकर गिर गए थे, उनके पैर में हेयरलाइन फ्रैक्चर है।

अपना काम जारी रखूंगा, लेकिन मुझे व्हीलचेयर का उपयोग करना होगा, कम से कम इस (बजट) सत्र के इस भाग में शामिल होने के लिये।” बजट सत्र का पहला भाग 13 फरवरी को समाप्त होने वाला है। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें बुरी नजर लग गई है, तो थरुर ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “लगे रहने दो (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प.बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस

खड़गे के आवास पर गुरुवार को हुई प्रदेश कांग्रेस की बैठक में हुआ बड़ा फैसला

—श्रीनंद झा—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 5 फरवरी। गठबंधन राजनीति में शामिल रहने के लगभग डेढ़ दशक के बाद, कांग्रेस ने आगामी पश्चिम बंगाल चुनावों में अकेले उतरने का फैसला किया है। 1970 के दशक तक प.बंगाल पर कांग्रेस का प्रभुत्व था पर बाद में धीरे-धीरे कांग्रेस कमजोर होती गई और उसकी खाली जगह पर पहले वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस का कब्जा है। गठबंधन राजनीति से जुड़ने से कांग्रेस को कोई खास लाभ नहीं हुआ। वर्ष 2011 में, कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और 42 सीटें जीतीं। वर्ष 2016 में, पार्टी ने माकपा के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा और 44 सीटें जीतीं। पिछले 2021 के चुनावों में, कांग्रेस ने फिर से माकपा नेतृत्व वाले वाम मोर्चे के साथ गठबंधन किया, लेकिन अपना खाता भी नहीं खोल सकी। पार्टी के राज्य नेतृत्व की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नई दिल्ली स्थित निवास, 10 राजाजी मार्ग पर गुरुवार को हुई बैठक के बाद “एकला चालो” निर्णय लिया गया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष

- डेढ़ दशक तक कभी वाम मोर्चा तो कभी तृणमूल के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस का मन लगता है अब भर चुका है।
- गत चुनाव कांग्रेस ने वाम मोर्चा के साथ लड़ा था पर पार्टी का खाता भी नहीं खुला ,इसलिए इस बार वाममोर्चा के साथ कांग्रेस गठबंधन नहीं करना चाहती और तृणमूल पार्टी का रवैया बेहद घमंडी है इसलिए कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी।
- सत्तर के दशक तक बंगाल की राजनीति में कांग्रेस का दबदबा था, धीरे-धीरे पार्टी कमजोर होती गई तो पहले वाम मोर्चा और फिर तृणमूल ने कांग्रेस की छोड़ी हुई जगह हथिया ली।

के नेता राहुल गांधी भी बैठक में मौजूद थे। बैठक में राज्य के नेताओं ने पार्टी नेतृत्व को बताया कि वाम मोर्चे के साथ गठबंधन से अब खास सफलता नहीं मिल रही है। क्योंकि वाम नेताओं ने कांग्रेस से “संसाधन तो खींचे, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में वोट ट्रांसफर करने में सक्षम नहीं हो सके”। उन्होंने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के साथ चुनावी समझौते को भी नकारात्मक रूप से देखा, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का रुख काफी “घमंडी और अक्खड़” था। पिछले विधानसभा चुनावों में, कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन नहीं कर पाई, क्योंकि तृणमूल ने कांग्रेस को “बेहद कम” सीटों का प्रस्ताव दिया था। राज्य के नेताओं ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस का यह मत था कि कांग्रेस सिदेबाजी करने की स्थिति में भी नहीं थी। ममता बनर्जी के भतीजे और वरिष्ठ तृणमूल नेता ने यहां तक कि सुझाव दिया था कि कांग्रेस को तृणमूल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

चुनावों में बढ़ते “रेवड़ी कल्चर” पर सुप्रीम कोर्ट का रुख गंभीर

सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस विषय पर गंभीर चिंतन की जरूरत है इसलिए इस पर तीन सदस्यीय बैंच विचार करेगी

— जाल खंभाता —
— राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो —
नई दिल्ली, 5 फरवरी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि चुनावी घोषणापत्र और चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त योजनाओं के वादे करने का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। यह सार्वजनिक हित से जुड़े गंभीर सवाल उठाता है और इस पर तीन जजों की बैंच को विचार करना चाहिए। यह टिप्पणी उस समय की गई जब भाजपा नेता और वकील याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की बैंच के सामने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने चुनावी घोषणापत्र और प्रचार के दौरान मुफ्त योजनाओं की घोषणा पर रोक लगाने की मांग की है। यह संकेत देते हुए कि मामला बड़ी बैंच के सामने रखा जाएगा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण

- मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत व जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बैंच ने याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय से कहा, यह जनहित का गंभीर मुद्दा है और इसे तीन सदस्यीय बैंच द्वारा सुना जाना चाहिए। इसे मार्च में सुना जाएगा तब तक इंतजार कीजिए।
- याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में चुनावों में मुफ्त सामान बांटने के “रेवड़ी कल्चर” पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि 5 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अब सिर्फ सूरज, चांद देने का वायदा किया जाना ही बचा है।
- राजनैतिक दलों ने इस याचिका का विरोध किया तथा इसे राजनैतिक रूप से प्रेरित बताया। उनका कहना है कि लोक कल्याणकारी योजनाएं व सब्सिडी शासन का अस्म भाग हैं इसका लक्ष्य कमजोर तबकों की मदद करना होता है।
- सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में भी सुनवाई के दौरान मुद्दे को जटिल बताया था और अपनी न्यायिक सीमाओं की मजबूरी का उल्लेख किया था।

और सार्वजनिक हित का मामला है... इसे तीन जजों की बैंच को सुनना होगा। मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस महीने के बाद मामले की सुनवाई होगी। उन्होंने कहा, “मार्च तक

इंतजार करें।” उपाध्याय ने अदालत से मामले की तुरंत सुनवाई करने का आग्रह किया, यह कहते हुए कि आने वाले महीनों में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले

हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल वोटरों को प्रभावित करने के लिए लगातार वादे कर रहे हैं, जो उनके अनुसार भ्रष्ट आचरण है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संसद में रणनीति पर विपक्ष के नेताओं की बैठक हुई

नयी दिल्ली, 05 फरवरी। विपक्ष के संसदीय दल के नेताओं की गुरुवार को संसद भवन परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राज्य सभा में

- खड़गे के चैंबर में हुई बैठक में सपा, शिवसेना (उद्धव), आरएसपी, मुस्लिम लीग आदि के नेता शामिल हुए।

दिए गए जवाब तथा अन्य मुद्दों को लेकर रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। बैठक संसद भवन परिसर में राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में हुई जिसमें संसद में सभी दलों ने एकजुट होकर सरकार को घेरने की रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया। बताया जाता है कि इसमें (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इण्डो-यूएस ट्रेड डील पर संयुक्त बयान की प्रतीक्षा में हैं विशेषज्ञ

अभी तक ना तो भारत की तरफ से ही ना ही अमेरिका की तरफ से डील पर कोई स्पष्ट बयान आया है

—अंजन रॉय—
—राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो—
नई दिल्ली, 5 फरवरी। भारत और अमेरिका के बीच जिस व्यापार समझौते की काफी चर्चा हो रही है, अब साफ होता जा रहा है कि वह ज्यादा से ज्यादा एक हार्ड प्रोफाइल दिखावा है। विशेषज्ञ दोनों देशों के संयुक्त बयान का इंतजार कर रहे हैं। भारत ने अब तक इस समझौते पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, अगर ऐसा कोई समझौता वास्तव में हुआ भी है। अमेरिका ने भी इस समझौते पर कोई विस्तार से बयान जारी नहीं किया है। अलग अलग संकेतों से पता लगाया जा सकता है कि भारत और अमेरिका, दोनों में इंडो-यू.एस. ट्रेड डील को लेकर क्या हो रहा था।

अमेरिका का दबाव भारत पर काम नहीं कर पाया और जब भारत अपनी बात पर अड्डा रहा, तो अमेरिकी पक्ष निराश हो गया। यह बात ट्रम्प के अधिकारियों और खुद डॉनल्ड ट्रम्प की भारत और उसकी आर्थिक संभावनाओं पर की गई टिप्पणियों से साफ नज़र आई। एक समय डॉनल्ड ट्रम्प ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मरी हुई कहा और अपमानजनक टिप्पणियां कीं। इन घटनाओं से भारतीय टीम और शीर्ष नेतृत्व नाराज हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉनल्ड ट्रम्प के फोन कॉल लेने से भी साफ इनकार कर दिया था। इसी पृष्ठभूमि में भारत और यूरोपीय संघ के बीच अचानक व्यापार समझौता होने और उसके चारों ओर बने कूटनीतिक माहौल ने अमेरिका को अलग-थलग कर दिया। डॉनल्ड ट्रम्प

- हालांकि, ट्रेड डील को लेकर अभी सिर्फ कयास ही लग रहे हैं लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अमेरिका की दबाव डालने की रणनीति भारत पर कारगर नहीं हुई और यूरोपियन यूनियन के साथ हुई ट्रेड डील से तो अमेरिका की हताशा और बढ़ गई।
- यही वजह रही कि कभी भारत को “डैड इकॉनमी” बताने वाले ट्रंप ने खुद ही ट्रेड डील स्वीकृत करने की घोषणा कर दी क्योंकि ट्रंप समझ गए कि भारत का विशाल बाजार उनके हाथ से निकल रहा है।
- घोषणा अमेरिका की तरफ से हुई और डील भी बेहद आकर्षक थी, ऐसे में भारत के इन्कार करने का सवाल नहीं था।
- पर अब देखना यह है कि वास्तव में यह डील क्या रूप लेती है और भारत को कितना लाभ देगी।

को अपने कट्टर दुश्मन, खासकर यूरोप और यूरोपीय संघ के सामने पीछे छूटना पसंद नहीं आया। ट्रम्प को खोई हुई जमीन को वापस पाने की तत्काल ज़रूरत महसूस हुई और वे मौके की तलाश में थे। उन्होंने वाशिंगटन से ट्रेड डील की एकतरफा घोषणा कर दी, जिससे भारतीय पक्ष हैरान रह गया। घोषित व्यापार समझौता भारत के लिए इतना आकर्षक बताया गया कि उसे केवल घोषणा कहकर ठुकराना मुश्किल था। हालांकि भारत ने यह नहीं कहा कि कोई पक्का व्यापार समझौता हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने सिंहाचार के तौर पर राष्ट्रपति की घोषणा का स्वागत किया। इस तरह अब केवल अमेरिका, खासकर राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प के बड़े

दावे ही बाकी रह गए हैं। यह अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए जोर-शोर से किया गया दावा है। ट्रम्प ने भारत से बहुत बड़ी मांग की थी। वह चाहते थे कि भारत में आने वाले अमेरिकी सामान पर सभी टैरिफ हटा दिए जाएं, जबकि अमेरिका भारतीय उत्पादों पर अपने शुल्क बनाए रखे। सही नहीं कहा जा सकता। भारत की ओर से इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि अमेरिकी सामान भारत में बिना शुल्क के आएगा। इसके बजाय कुछ बातों से संकेत मिले हैं कि तय कार्यक्रम के अनुसार भारत में आने वाले सामान पर चरणबद्ध तरीके से शुल्क लगाए जाएंगे। यह संभव नहीं है कि भारत सभी अमेरिकी आयात पर छूट दे, जबकि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गुरुवार को ठप्प रही लोकसभा

नयी दिल्ली, 05 फरवरी। लोकसभा में गुरुवार को भी विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी जारी रही जिसके कारण सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। तीन बार स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर तीन बजे शुरू होते ही विपक्षी सदस्य फिर से नारेबाजी करने

- लोकसभाध्यक्ष ने दिन भर के लिए कार्यवाही स्थगित करते हुए कहा सदस्य पोस्टर लेकर आएं तो सदन नहीं चलेगा।

लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामे के बीच कहा कि बड़े दुख के साथ सभा को सूचित करना है कि कल कुछ सदस्यों ने जिस प्रकार का व्यवहार किया और ऐसे दृश्यों का सुजन किया, वह लोकसभा के शुरुआत से लेकर आज तक आज तक कभी नहीं हुआ। संसदीय प्रणाली में सदन के समापति का परिणामय स्थान हमारे संविधान में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

बच्चों को पालना, उन्हें अच्छे व्यवहार की शिक्षा देना भी सेवाकार्य है, क्योंकि यह उनका जीवन सुखी बनाता है। –स्वामी रामसुखदास

लोकलुभावन नहीं 2047 के भारत की इबारत है नया बजट

संभवतः यह पहला अवसर होगा जब केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश करते समय चुनावों में राजनीतिक लाभ हानि पर विचार किये बिना समग्र विकास और दीर्घकालीन आर्थिक सुधार को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। कुछ माहों में ही पं. बंगाल, तमिलनाडू, केरल, असम और पुडुचेरी के चुनाव की तिथियां घोषित हो जाएगी। अब तक होता यह आया है कि बजट में चुनाव वाले राज्यों के नागरिकों को लुभाने के लिए खास घोषणाएं होती हैं। पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजनीतिक लाभ हानि के स्थान पर समग्र सुधारों और सरकार के मिशन 2047 को केन्द्र में रखकर 2027-28 का बजट पेश किया है। निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वां बजट पेश किया है। खासबात यह कि 2019 से 2026 तक लगातार नवां बजट पेश करने तक वित्त मंत्री सीतारमण भिन्न भिन्न प्रदेशों की हथकरघा साड़ियों में नजर आई है। इस बार तमिलनाडू की बैंगनी कांजीवरम सिल्क साड़ी में नवां बजट पेश किया।

इस साल का बजट इसलिए भी मायने रखता है कि दुनिया के देशों के हालात और वैश्विक परिस्थितियां दिन प्रतिदिन विपरीत होती जा रही हैं। बजट के दिन जहां शेयर बाजार धराशाही हो गया वहीं दूसरे दिन ही अमेरिका द्वारा टैरिफ दर कम करने के साथ ही शेयर बाजार ने उंची उड़ान भर डाली। पर वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए भारत की आर्थिक विकास की गति बनाए रखना किसी गंभीर चुनौती से कम नहीं है। विपरीत हालातों में भी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हमारी है। दुनिया के देश जहां आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था ने उंचाई प्राप्त की है। अमेरिका में ट्रंप 2 के बाद से दुनिया के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं पर जिस रणनीति से भारत ने अमेरिका को इन्फोर की नीति पर चलते हुए चुनौती दी इसी का परिणाम है कि ट्रंप को टेरिफ दरें घटानी पड़ी है। हालांकि ट्रंप के मिजाज को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब बह पलटी मार जाए।

केन्द्रीय बजट की इसलिए सराहना की जानी चाहिए कि वैश्विक हालातों को देखते हुए दीर्घकालीन आर्थिक सुधार, देश में ढांचगत विकास और युवाओं, महिलाओं, किसानों सभी को साधने का जो समग्र प्रयास हुआ है उससे निश्चित रूप से आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को नई दिशा मिलेगी। विश्लेषक इसे समग्र सुधारों के साथ विकास का संकल्प बता रहे हैं तो कोई इस बजट को भारत की

आत्मनिर्भरता का कवच बता रहे हैं।

कहने को लाख आलोचनाएं की जा सकती हैं पर वैश्विक हालातों को देखते हुए जिस तरह का भविष्योन्मुखी ठोस आधारभूत विकास का बजट होने से इससे दीर्घकालीन लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट प्राप्त होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बजट के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि लोकलुभावन ही नहीं आमजन दीर्घकालीन आर्थिक विकास के बजट का आगे बढ़कर स्वागत करते हैं। अब बजटीय व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन का भी समयबद्ध रोडमैप बन जाए तो निश्चित रूप से इसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा।

युद्ध में बदल जाएं कहा नहीं जा सकता है और पाकिस्तान कब अपनी उद्दंडता दिखा दे कुछ कहा नहीं जा सकता, चीन के इरादे हमेशा संदिग्ध रहे हैं ऐसे में रक्षा क्षेत्र में बजटीय प्रावधान बढ़ाना और सैन्य क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाना समय की मांग है। इसी तरह से डिजिटल युग में दुनिया के देशों से दो कदम आगे बढ़ना समय की मांग है। एआई के युग को देखते हुए एआई को रोजगार का माध्यम बनाना, कौशल विकास, तकनीक से शिक्षा को जोड़ने, पर्यटन विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, यहां तक कि गाइड्स तैयार करने से लेकर चुनावों और रोजगार से जुड़े सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के प्रावधान किये गये हैं। खेती-किसानी को प्रोत्साहित करने के साथ ही जल के महत्व को समझा गया है। अमृत सरोवर से जल संग्रहण से लेकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बेहतर लोजिस्टिक प्रमुख आवश्यकता है। रक्षा के बाद सबसे अधिक प्रावधान बेहतर कनेक्टिविटी को दिया गया है। बेहतर आवागमन से विकास को गति मिलती है तो योजनाबद्ध शहरी विकास पर जोर दिया गया है। यदि सार रूप में कहा जाए तो यह बजट आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने का रोडमैप कहा जा सकता है। विनिर्माण क्षेत्र को गति, आधारभूत संरचना विकास, कौशल विवकास, एमएसएमई को प्रोत्साहन, उर्जा विकास व सहज उपलब्धता, इकोसिस्टम बनाए रखते हुए समग्र विकास पर जोर रहा है। हालांकि नौकरी पेशा लोग आयकर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करने से निराश हुए हैं तो शेयर मार्केट में सर्ट्देबाजी को निरुत्साहित करने से निराशा हुई और इसका तत्काल असर शेयर बाजार पर देखा गया। कहने को लाख आलोचनाएं की जा सकती है पर वैश्विक हालातों को देखते हुए जिस तरह का भविष्योन्मुखी ठोस आधारभूत विकास का बजट होने से इससे दीर्घकालीन लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट प्राप्त होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बजट के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि लोकलुभावन ही नहीं आमजन दीर्घकालीन आर्थिक विकास के बजट का आगे बढ़कर स्वागत करते हैं। अब बजटीय व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन का भी समयबद्ध रोडमैप बन जाए तो निश्चित रूप से इसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा।

–अतिथि सम्पादक,
डॉ.राजेन्द्र प्रसाद शर्मा
(वरिष्ठ लेखक)

राशिफल

शुक्रवार 6 फरवरी, 2026

फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, हस्त नक्षत्र रात्रि 12:2 तक, धृति योग रात्रि 11:37 तक, कौलव करण दिन 12:51 तक, चन्द्रमा आज कन्या राशि में संचार करेगा।

गृहस्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज कुमार योग सूर्योदय से रात्रि 12:24 तक है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:36 तक, लाभ-अमृत 8:36 से 11:19 तक, शुभ 12:41 से 2:03 तक, चर 4:46 से सूर्यास्त तक।
राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 6:08



मेघ

परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होंगे। अस्त-व्यस्त दिवचार्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



तुला

व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। नौकरपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। आर्थिक मामलों में पेशानी हो सकती है। मन में असंतोष बना रहेगा।



वृष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



वृश्चिक

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।



मिथुन

घर-परिवार में सुख-शान्ति बनी रहेगी। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी।



धनु

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



मकर

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कुंभ

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है।



सिंह

आर्थिक/वित्तीय मामलों में संतुलन बना रहेगा। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।



मीन

परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।



कन्या

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेगे। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

ट्रंप डील और मोदी नेतृत्व

राजस्थान के उद्योग के लिए नए अवसरों का द्वार



अशोक परनामी

भारत और अमेरिका के बीच लंबे इंतजार के बाद संपन्न हुई नई ट्रेड डील ने न केवल दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई दी है, बल्कि राजस्थान जैसे निर्यात-आधारित राज्यों के लिए यह समझौता उम्मीदों का नया क्षितिज खोलता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारतीय उत्पादों पर टैरिफ की घटाकर 18 प्रतिशत करने का निर्णय ऐसे समय आया है, जब वैश्विक बाजार में अस्थिरता और संरक्षणवाद

की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। इस प्रष्ठभूमि में यह समझौता भारत की बढ़ती वैश्विक साख और प्रभावी आर्थिक कूटनीति का प्रमाण माना जा रहा है। इस ऐतिहासिक समझौते के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बीते एक दशक में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद वैश्विक साझेदार के रूप में स्थापित किया है। 'मेक इन इंडिया', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' जैसे अभियानों को अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता दिलाने में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। अमेरिका जैसे प्रभावशाली देश द्वारा टैरिफ में इतनी बड़ी कटौती इस बात का संकेत है कि भारत अब शर्तें तय करने वाली अर्थव्यवस्था बन रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इस डील को 'गेम चेंजर' करार देना भी इसी तथ्य को रेखांकित करता है कि केंद्र के मजबूत नेतृत्व का सीधा लाभ राज्यों तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले छह वर्षों में

ऊर्जा मिली है। अमेरिका जैसे बड़े खरीदार पर काफी हद तक निर्भर स्टोन इंडस्ट्री टैरिफ बढ़ने से सबसे अधिक प्रभावित हुई थी। 70 प्रतिशत से अधिक इकाइयों पर इसका नकारात्मक असर पड़ा। अब टैरिफ कटौती के बाद अमेरिकी खरीदारों की सक्रियता बढ़ने से उत्पादन और रोजगार दोनों में सुधार की उम्मीद है। इसी तरह तीन लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला जयपुर का गारमेट उद्योग एक बार फिर रफ्तार पकड़ने को तैयार है। निर्यात में गिरावट से जूझ रहे एमएसएमई सेक्टर के लिए यह समझौता विशेष रूप से राहतभरा साबित हो रहा है। राजस्थान का हस्तशिल्प, ब्लू पॉर्टी, लकड़ी का काम, संगमरमर की नक्काशी और हाथ से बने वस्त्र अमेरिकी बाजार में लोकप्रिय रहे हैं। टैरिफ घटने से जयपुर और जोधपुर के कारीगरों को बेहतर दाम और स्थिर बाजार मिलने की संभावना है। यह न केवल आर्थिक लाभ देगा, बल्कि सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी

सहायक होगा। निर्यात में वृद्धि का असर केवल उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगा। परिवहन, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, बैंकिंग और बीमा जैसे सहायक क्षेत्रों में भी गतिविधियां बढ़ेंगी। यह 'मल्टीप्लायर इफेक्ट' राजस्थान की अर्थव्यवस्था को व्यापक गति देगा और नए रोजगार सृजित करेगा।

भारत-अमेरिका ट्रेड डील और टैरिफ में ऐतिहासिक कटौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट दृष्टि और प्रभावी आर्थिक कूटनीति का परिणाम है। राजस्थान के लिए यह समझौता केवल व्यापारिक राहत नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ वैश्विक बाजार में आगे बढ़ने का अवसर है। यदि राज्य और केंद्र सरकार के प्रयासों के साथ उद्योग जगत इस अवसर का सही उपयोग करता है, तो राजस्थान आने वाले वर्षों में निर्यात के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू सकता है और यही इस डील की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी।
—अशोक परनामी,
पूर्व विधायक एवं पूर्व मेयर जयपुर।

तारबंदी से सुरक्षा, बीमा से संबल : किसानों को करोड़ों रुपये का अनुदान मिला

विकसित भारत 2047 के सपने के केंद्र में अन्नदाता : सरकारी सहायता और योजनाओं ने खोले रास्ते, किसान ने दुनिया देखी



अमृता कटारा

भारतीय कृषि को अक्सर परंपरा के फ्रेम में बाँधकर देखा गया है—हल, बैल, मानसून और अनिश्चितता। लेकिन आज खेतों की ज़मीन के नीचे सिर्फ बीज नहीं, बदलाव भी दबाहुआ है। यह बदलाव न तो अचानक है और न ही पूरी तरह दृश्यमान होता है। यह धीरे-धीरे किसान की सोच, नीति और खेती में बदलाव की कोशिश कर रही है। एक ओर रक्षा बजट की कोशिश कर रही है। जिस तरह के तनाव के हालात बने हुए हैं और हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के हालात रहे, उधर रुस यूक्रेन युद्ध थमने का ही नाम नहीं ले रहा है, ईरान अमेरिका के हालात कब

युद्ध में बदल जाएं कहा नहीं जा सकता है और पाकिस्तान कब अपनी उद्दंडता दिखा दे कुछ कहा नहीं जा सकता, चीन के इरादे हमेशा संदिग्ध रहे हैं ऐसे में रक्षा क्षेत्र में बजटीय प्रावधान बढ़ाना और सैन्य क्षेत्र को और अधिक सशक्त बनाना समय की मांग है। इसी तरह से डिजिटल युग में दुनिया के देशों से दो कदम आगे बढ़ना समय की मांग है। एआई के युग को देखते हुए एआई को रोजगार का माध्यम बनाना, कौशल विकास, तकनीक से शिक्षा को जोड़ने, पर्यटन विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, यहां तक कि गाइड्स तैयार करने से लेकर चुनावों और रोजगार से जुड़े सभी क्षेत्रों को आगे बढ़ाने के प्रावधान किये गये हैं। खेती-किसानी को प्रोत्साहित करने के साथ ही जल के महत्व को समझा गया है। अमृत सरोवर से जल संग्रहण से लेकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बेहतर लोजिस्टिक प्रमुख आवश्यकता है। रक्षा के बाद सबसे अधिक प्रावधान बेहतर कनेक्टिविटी को दिया गया है। बेहतर आवागमन से विकास को गति मिलती है तो योजनाबद्ध शहरी विकास पर जोर दिया गया है। यदि सार रूप में कहा जाए तो यह बजट आर्थिक विकास की गति को बनाए रखने का रोडमैप कहा जा सकता है। विनिर्माण क्षेत्र को गति, आधारभूत संरचना विकास, कौशल विवकास, एमएसएमई को प्रोत्साहन, उर्जा विकास व सहज उपलब्धता, इकोसिस्टम बनाए रखते हुए समग्र विकास पर जोर रहा है। हालांकि नौकरी पेशा लोग आयकर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं करने से निराश हुए हैं तो शेयर मार्केट में सर्ट्देबाजी को निरुत्साहित करने से निराशा हुई और इसका तत्काल असर शेयर बाजार पर देखा गया। कहने को लाख आलोचनाएं की जा सकती है पर वैश्विक हालातों को देखते हुए जिस तरह का भविष्योन्मुखी ठोस आधारभूत विकास का बजट होने से इससे दीर्घकालीन लाभ मिलेगा और अर्थव्यवस्था को बूस्ट प्राप्त होगा। सबसे खास बात यह है कि इस बजट के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि लोकलुभावन ही नहीं आमजन दीर्घकालीन आर्थिक विकास के बजट का आगे बढ़कर स्वागत करते हैं। अब बजटीय व्यवस्थाओं के क्रियान्वयन का भी समयबद्ध रोडमैप बन जाए तो निश्चित रूप से इसका वास्तविक लाभ मिल सकेगा।

शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कृषि की नीति के केंद्र में रखा है। किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, पीएम-कुसुम, अटल भू-जल योजना, किसान डिजिटल आईडी, तारबंदी और जैविक खेती जैसी योजनाएँ यह संकेत देती हैं कि सरकार ने खेती को अल्पकालिक राहत नहीं, बल्कि दीर्घकालिक योजना मानती है। राज्य सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 59 हजार 039 सोलर पंपसेटों की स्थापना कर 900 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिया जाना यह बताता है कि सिंचाई और नवीनीकरण ऊर्जा के सवाल को स्थायी समाधान की ओर ले जाया जा रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लगभग 6,450 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम का वितरण यह दर्शाता है कि प्राकृतिक आपदाओं के समय किसान को आर्थिक सुरक्षा देने का प्रयास किया गया है। खेती में जोखिम कम हुए बिना नवाचार संभव नहीं होता। नीति का असर तब स्पष्ट दिखता है जब वह ज़मीन पर उतरती है।

राजस्थान में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर इस मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो रहे हैं। योजनाओं की जानकारी, आवेदन की प्रक्रिया और समस्याओं का समाधान—सब कुछ एक ही मंच पर उपलब्ध होने से किसानों और प्रशासन के बीच की दूरी कम हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मानना है कि जागरूकता केवल सूचना से नहीं, संवादसे आती है और यही इन शिविरों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। प्रतापगढ़ जैसे जनजाति क्षेत्रों में यह बदलाव विशेष महत्व रखता है, जहाँ खेती लंबे समय तक केवल जीवन निर्वहण तक सीमित रही। छोटी ज़ोतों और सीमित संसाधनों के बीच प्रतापगढ़ के जवाहरनगर के बाबूलाल मीणा द्वारा सरकार की सहायता से वर्मी कम्पोस्ट यूनित की स्थापना यह बताती है कि जैविक खेती अब प्रयोग नहीं रही। कम लागत, बेहतर मूल्य और अतिरिक्त आय—ये



परिणाम बताते हैं कि सही मार्गदर्शन मिलने पर किसान टिकाऊ विकल्पों की ओर बढ़ सकता है।

इसी जिले से किसान शंभूलाल पाटीदार का डेनमार्क एक्सपोजर विजिट पर जाना यह संकेत देता है कि कृषि प्रशिक्षण अब केवल तकनीक सिखाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सोच का दायरा भी बढ़ा रहा है। जब किसान दुनिया को देखने लगता है, तो अपनी ज़मीन को देखने का नज़रिया भी बदल जाता है। तारबंदी योजना ने भी खेती को स्थिरता दी है एवं किसानों के हितों की रक्षा की है। जवाहरनगर की दुग्रां बाई मीणा और पिल्लू गाँव के पंकज कुमार मीना जैसे किसानों की कहानियाँ यह बताती हैं कि फसल सुरक्षा केवल नुकसान नहीं रोकती बल्कि कृषि को अधिक सुरक्षित बनाती है।

राज्य में लगभग 34,395 किलोमीटर तारबंदी कर 377.66 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाना इस बात का संकेत है कि खेती को जोखिम से मुक्त करने की दिशा में ठोस प्रयास हुए हैं। इसके साथ ही 35,368 फार्म पॉन्ड के निर्माण पर 300 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जल संरक्षण को खेती की बुनियाद बनाने की मंशा को दर्शाता है। इन सभी अनुभवों और आँकड़ों को साथ रखकर देखा जाए तो स्पष्ट होता

है कि प्रदेश के अन्नदाताओं का भविष्य जनहितैषी कार्यों की निरंतरता, ज़मीनी क्रियान्वयन और किसान की भागीदारी से आकार ले रहा है। खेत आज भी परंपरा से जुड़े हैं, लेकिन अब उनके साथ सुरक्षा, ज्ञान और उम्मीद भी खड़ी है—और शायद यही बदलाव की सबसे बड़ी पहचान है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कृषि को नवाचार, सुरक्षा और सम्मान से जोड़ने की दिशा में जो व्यापक विजन सामने रखा, उसे राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में ज़मीन पर आकार मिलता दिख रहा है। सोलर पंप से लेकर फसल बीमा, तारबंदी से लेकर जल संरक्षण तक—ये प्रयास यह संकेत देते हैं कि किसान को अब केवल उत्पादन की इकाई नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का सहभागी माना जा रहा है। जनजाति क्षेत्रों से सामने आई बदलाव की यह कहानियाँ यह भरोसा जगाती हैं कि जब नीति में निरंतरता हो और क्रियान्वयन में संवेदनशीलता, तो खेती केवल अतीत की विरासत नहीं रहती, वह भविष्य की बुनियाद बन जाती है।

शंभू लाल पाटीदार: वैश्विक अनुभव और सरकारी योजनाओं से बदली खेत की तस्वीर। प्रतापगढ़ जिले के प्रगतिशील किसान शंभू लाल पाटीदार ने पारंपरिक

खेती को आधुनिक और लाभकारी कृषि में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। उन्होंने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और पीएम सूर्य घर योजना जैसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी खेती को नई दिशा दी। सरकारी सहयोग से वे पॉलीहाउस में लाल और हरी शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, जिससे उन्हें अधिक उत्पादन के साथ बेहतर बाजार मूल्य भी मिल रहा है। उनकी यह सफलता इस बात का उदाहरण है कि सही तरीके से लागू की गई सरकारी योजनाएं किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ टिकाऊ और नवाचारी कृषि को भी बढ़ावा देती हैं।

हाल ही में शंभू लाल पाटीदार को एक सरकारी कार्यक्रम के तहत डेनमार्क जाने का अवसर मिला, जहाँ उन्होंने उन्नत जैविक खेती की तकनीकों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने इस अनुभव को अत्यंत लाभकारी बताते हुए कहा कि वहां उन्होंने उत्पादन बढ़ाने और खेती में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने के कई महत्वपूर्ण गुर सीखे। सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह की पहल किसानों को वैश्विक ज्ञान, नई दक्षताएं और नवाचार करने का आत्मविश्वास प्रदान करती हैं।

—अमृता कटारा,
एपीआरओ, डीआईपीआर

बोर्ड परीक्षाओं के लिए कंट्रोल रूम शुरु

अजमेर, (निर्स)। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12 फरवरी से शुरू होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के सफल, निष्पक्ष एवं सुचारु आयोजन को लेकर गुरुवार को कंट्रोल रूम की स्थापना की गई। इस अवसर पर बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठी ने विधि-विधान के साथ मां सरस्वती की पूजा-अर्चना कर कंट्रोल

बोर्ड का शुभारंभ किया। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठी ने जानकारी देते हुए बताया कि कंट्रोल रूम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य परीक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना तथा परीक्षा के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। कंट्रोल रूम

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अधिकारियों परीक्षा के दौरान आने वाली किसी भी प्रकार की परीक्षा, अव्यवस्था या आपात स्थिति की जानकारी सीधे कंट्रोल बोर्ड को दे सकेंगे। प्राप्त सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बोर्ड प्रशासन का मानना है कि कंट्रोल बोर्ड की सक्रिय

अधीक्षक एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी परीक्षा के दौरान आने वाली किसी भी प्रकार की परीक्षा, अव्यवस्था या आपात स्थिति की जानकारी सीधे कंट्रोल बोर्ड को दे सकेंगे। प्राप्त सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई कर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बोर्ड प्रशासन का मानना है कि कंट्रोल बोर्ड की सक्रिय

भूमिका से परीक्षा संचालन में पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या तकनीकी समस्या पर तुरंत नियंत्रण पाया जा सकेगा। इससे न केवल परीक्षा केंद्रों को मार्गदर्शन मिलेगा, बल्कि विद्यार्थियों को भी शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में परीक्षा देने का अवसर मिलेगा।



पंडित अनिल शर्मा

में संचार करेगा।

गृहस्थिति: सूर्य-मकर, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-मकर, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-कुम्भ, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह आज कुमार योग सूर्योदय से रात्रि 12:24 तक है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:36 तक, लाभ-अमृत 8:36 से 11:19 तक, शुभ 12:41 से 2:03 तक, चर 4:46 से सूर्यास्त तक।
राहुकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:14, सूर्यास्त 6:08

सिनेमा जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए 9 प्रतिभाओं को विशेष अवार्ड

जोधपुर, (का.सं.)। पूर्व महाराजा गजसिंह एवं पूर्व महारानी हेमलता राज्य के मुख्य आतिथ्य में ऐतिहासिक मेहरानगढ़ दुर्ग में आयोजित हुए 12 वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह एवं मेगा अवार्ड नाइट में भारतीय और अंतरराष्ट्रीय सिनेमा जगत की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए स्पेशल अवार्ड्स से सम्मानित किया। इस अवसर पर सिनेमा, अभिनय, निर्देशन, लेखन और तकनीकी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 87 प्रतिभाओं को भी सम्मानित किया गया।

समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए गज सिंह ने कहा कि सिनेमा एक ऐसा सशक्त माध्यम में जो विभिन्न संस्कृतियों को आपस में जोड़ता और समाज की श्रेष्ठ रचनात्मकता को सामने लाता है । उन्होंने कहा कि राजस्थानी भाषा में फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और टेलीविजन धारावाहिको के निर्माण पर विशेष जोर देते हुए ताकि राजस्थानी एक समृद्ध भाषा है जो लोगों को भरपूर मनोरंजन करने के साथ उनकी संस्कृति पहचान को भी मजबूत करती है

उन्होंने बताया कि राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से जोधपुर तक संस्कृति, समझ और जानकारी पहुंची जिससे शहर को बड़ा लाभ हुआ है ।

रिफ फाउंडर व फेस्टिवल डायरेक्टर सोमैत्र हर्ष ने बताया कि अवार्ड सेरेमनी ने सिनेमा, संस्कृति और राजस्थान को विरासत को एक मंच पर खूबसूरती से प्रस्तुत किया। पाँच दिनों तक चले इस आयोजन के दौरान 78 से अधिक हिंदी, इंग्लिश और राजस्थानी सहित विभिन्न श्रेणियों की फिल्में



जोधपुर में गज सिंह व हेमलता राज्य के मुख्य आतिथ्य में 12 वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का समापन समारोह एवं मेगा अवार्ड नाइट आयोजित हुई।

प्रदर्शित की गईं, जिनमें फीचर फिल्में, शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्री शामिल रही।निदेशक अंशु हर्ष ने रिफ के सफल आयोजन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया।

अभिनेता और मशहूर कवि शैलेश लोढ़ा ने कहा कि मारवाड़ की कला, संस्कृति, संगीत और साहित्य के प्रति लोगों का अनुराग अद्भुत है और उन्हें अपने शहर पर गर्व है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति भले ही मारवाड़ से बाहर चला जाए, लेकिन मारवाड़ उसके भीतर सदैव जीवित रहता है। उन्होंने युवाओं से अन्य भाषाएँ सीखने के साथ-साथ मारवाड़ी भाषा और संस्कृति को संरक्षने की अपील की। इसी अवसर पर उन्होंने

अपने पिता श्याम सिंह लोढ़ा की स्मृति में घोषणा की कि अगले वर्ष राजस्थान में बनने वाली फीचर फिल्मों को दो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिए जाएंगे, जिनकी राशि एक लाख रुपये और पचास हजार रुपये होगी।

अभिनेता रजत कपूर ने कहा कि यह सम्मान उनके लिए एक बड़ा और अप्रत्याशित आश्चर्य है। वे यहां फिल्म में देखने और अपनी शॉर्ट फिल्मों को प्रस्तुत करने आए थे, लेकिन इस तरह का पुरस्कार मिलने की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी।

उन्होंने कहा कि एक अभिनेता के रूप में निरंतर सीखते रहना और आगे बढ़ने की कोशिश करना उनका कर्तव्य

है। रंगमंच हमेशा उनके जीवन का अहम हिस्सा रहा है और सिनेमा व थिएटर का यह सफर आगे भी जारी रहेगा।

रजत कपूर ने बताया कि बीते दिनों में उन्होंने पैदल पूरे पुराने शहर को देखा, ओसियां तक गए और अब उन्हें जोधपुर की हवा और माहौल से गहरा जुड़ाव महसूस हो रहा।

फिल्म अभिनेता मकरंद देशपांडे ने कहा कि किसी कलाकार के लिए पुरस्कार मिलना बड़ी बात नहीं होती, बल्कि यह अधिक महत्वपूर्ण है कि वह सम्मान किस स्थान पर मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि मेहरानगढ़ किला अपने आप में इतिहास, कला और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है। ऐसे

पोलेण्ड में नौकरी का झांसा, ठगी की

जोधपुर, (कासं) । शहर के रातानाडा स्थित भास्कर चौराहा के पास चलने वाले विक्टोरियन इंग्लिश हब के कामकों ने मिलकर एक युवक को विदेश भेजने का झांसा देकर उससे 6 लाख रूपयों की ठगी कर ली। पीड़ित को ना तो विदेश भेजा गया और ना ही दिए गए दस्तावेज वापिस लौटाए गए। पीड़ित युवक को जान की धमकी दी जा रही है। इस बारे में रातानाडा थाने में केस दर्ज कराया गया है।

मूलतः बाड़मेर के शिव तहसील के मोखाव कलां पंचायी की ठाणी हाल रातानाडा गणेश मंदिर के पास रहने वाले ओमप्रकाश पुत्र खेराबराम जाट ने रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसकी जान पहचान रातानाडा भास्कर चौराहा स्थित विक्टोरियन इंग्लिश हब की तमन्ना सेवड़ से साल 2023 को हुई थी। तब उसने बताया कि उसके पास पोलेण्ड में नौकरी लगवाने का ईतजाम है। इस पर उसकी बातों का विश्वास कर पीड़ित ने 4 लाख 5 हजार रूपए केश दिए। बाकी रकम वीजा मिलने के बाद देने को कहा गया। वीजा आने के बाद इस पर तमन्ना को बाद में 11 सितंबर 23 को 50 हजार, 24 सितंबर को 70 हजार, 26 मार्च 24 को 70 हजार, 4 जुलाई 90 हजार रूपए गुगल पे से किए गए थे। इस तरह कुल छह लाख रूपए उसे दिए गए। बाद में जब नौकरी के लिए दबाव बनाया गया तो वह टालमटोल जवाब मिला। हब चलाने वाले कार्मिकों ने उससे विदेश भेजने के नाम पर छह लाख रूपए एंटे लिए, मगर नहीं भेजा गया। बाद में धमकियां दी गईं।

इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार, तहसीलदार अमीन खान समेत विभिन्न जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं लोग उपस्थित रहे।

सास-बहू ने खेजड़ी बचाने के लिए खाना-पानी छोड़ा

जैसलमेर, (नि.सं.)। बीकानेर में चल रहे खेजड़ी बचाओं आंदोलन अब पश्चिमी राजस्थान के घेरों तक पहुंच गया है। जैसलमेर के एक परिवार में सास-बहू ने खेजड़ी बचाने के लिए खाना-पानी छोड़ दिया है। जैसलमेर जिले के लाठी गांव में पर्यावरण प्रेमी राधेश्याम की 23 मई 2025 को मौत हो गई थी। बेटा नहीं रहा तो उनकी मां रतनी देवी और पत्नी निरमा विश्वनोई दोनों ने घर पर अनशन शुरू कर दिया है।

मां बोली- जहां भी हिरणों के शिकार और पेड़ों की कटाई की बात आती, मेरा बेटा राधेश्याम सबसे आगे रहता था। अब वह दुनिया में नहीं है तो उसके अपूर्व मिशन को पूरा करने के लिए बहू के साथ अनशन पर बैठी हूं। शहीद राधेश्याम की वृद्ध माता रतनी देवी को बेटे के खोने का गम है। लेकिन, खेजड़ी बचाओं आंदोलन में बेटे क कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने बहू निरमा के साथ मंगलवार से खाना-पीना छोड़ दिया है। अनशन पर बैठी राधेश्याम की पत्नी निरमा विश्वनोई ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष है। यदि इसे नहीं बचाया गया तो हमारा पशुपालन, ठामीण अर्थव्यवस्था और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र तबाह हो जाएगा।

उन्होंने मांग की है कि सरकार केवल आशवासन न दे, बल्कि खेजड़ी संरक्षण के लिए प्रभावी कानून और ठोस नीति लागू करें। उनका संकल्प है कि जब तक बीकानेर में चल रहे महापड़ाव की मांगें नहीं मानी जातीं, वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगी।

खेजड़ी के अवैध कटान पर सख्त कानून की मांग

भीनमाल, (नि.सं)। जालोर जिले सहित कई जगहों पर खेजड़ी के वृक्षों की लगातार हो रही अवैध कटाई को लेकर पर्यावरण प्रेमियों एवं बिश्नोई समाज के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर कड़ा विरोध जताया। ज्ञापन में खेजड़ी के अवैध कटान पर तत्काल रोक लगाने तथा दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।

तहसीलदार भीखदान चारण को मार्फत उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम सौंप गए ज्ञापन बताया गया कि जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बिना प्रशासनिक अनुमति के खेजड़ी वृक्षों का बड़े पैमाने पर कटान किया जा रहा है। कुछ सौर ऊर्जा कंपनियों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा नियमों की

अनदेखी कर पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई जा रही है, जो अत्यंत चिंताजनक विषय है। प्रतिनिधियों ने कहा कि खेजड़ी वृक्ष ने केवल राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि मरुस्थलीय पारिस्थितिकी संतुलन, पर्यावरण संरक्षण एवं किसानों की आजीविका का भी प्रमुख आधार है। बिश्नोई युवा जिलाअध्यक्ष एडवोकेट श्रवण ढाका ने बताया किखेजड़ी के अवैध कटान में संलिप्त दोषियों पर कम से कम 2 लाख का अर्थदंड तथा न्यूनतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति या कंपनी इस प्रकार के पर्यावरण अपराध को अंजाम देने का साहस न कर सके। ज्ञापन की प्रतिलिपि पर्यावरण एवं वन मंत्री तथा राजस्थान के राज्यपाल को भी भेजी गई है।

इस अवसर पर शिक्षक संघ प्रदेश महामंत्री राजुराम सारण, बार अभिभाषक संघ अध्यक्ष रघुनाथाराम सियाग, बिश्नोई समाज ट्रस्ट भीनमाल सचिव शिवनारायण बिश्नोई, बिश्नोई युवा जिलाध्यक्ष श्रवण ढाका, शिक्षक नेता किशनलाल जाजू , युवा उध्मी देवाराम झॉवर, रघुनाथाराम खिलेरी, शिक्षक संघ अध्यक्ष ब्लाक बागोडा चौथाराम बिश्नोई, ललिता बिश्नोई, राजुराम साऊ आदि मौजूद रहे।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल पर सम्मानित होना हर कलाकार के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है।

रिफ 2026 में भारतीय सिनेमा में दीर्घकालीन और उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध अभिनेता रजित कपूर को लीजेंडरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ,अंतरराष्ट्रीय सिनेमा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दीना रोजनमेयर को ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस , राजस्थान की कला और संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने वाले कवि, लेखक और टीवी कलाकार शैलेश लोढ़ा को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड , भारतीय सिनेमा में कार्टिंंग और प्रतिभाओं को पंच देने में अहम भूमिका निभाने वाले कार्टिंंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा को ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस , थिएटर, टेलीविजन और सिनेमा में सशक्त अभिनय के लिए जानी जाने वाली वरिष्ठ अभिनेत्री जयति भाटिया को भारतीय सिनेमा एवं टीवी में योगदान हेतु ऑनरेरी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस , अभिनेता और टीवी होस्ट अनुप सोनी को भारतीय सिनेमा और टेलीविजन में उनके प्रभावशाली अभिनय और योगदान के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया।

सिनेमा जगत में लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखिका और अभिनेत्री सीमा कपूर को बेस्ट ऑथर इन द फील्ड ऑफ सिनेमा अवार्ड , युवाओं के लिए प्रेरणास्त्रोत और राजस्थान से उभरती प्रतिभा शहजाद अली को यूथ आइकन ऑफ राजस्थान अवार्ड , रिफ -2026 के तहत राजस्थान की संस्कृति और कहानियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ाने के लिए अवार्ड प्रदान किया गया।

पाली में भाटी ने बाल गृहों का निरीक्षण किया



राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) विक्रम सिंह भाटी ने पाली जिले के बाल गृहों का निरीक्षण किया। फोटो-राष्ट्रदूत

पाली, (नि.सं.)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला न्यायाधीश) विक्रम सिंह भाटी द्वारा पाली जिले के बाल गृहों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाल गृह के भवन की स्वच्छता, बालकों के लिए उपलब्ध कपड़े, बिस्तर, भोजन एवं आहार, चिकित्सा सुविधाएं, पालनागृह तथा सभन की समटा स्थिति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण सचिव भाटी ने सम्प्रेषण गृह में आवासित बालकों से संवाद कर उन्हें मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता, खेलावली, पढ़ाई एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बाल कल्याण समिति एवं गृह स्टाफ को निर्देश दिए कि बालकों को गृह में प्रवेश दिलाए जाने के समय उनके परिवारजनों एवं रिश्तेदारों को शीघ्र सूचित किया जाए तथा सम्प्रेषण गृह में आवासित बालकों को बाल न्याय मित्र की सेवाएं तत्काल उपलब्ध करवाई जाएं।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में बालकों के मनोरंजन एवं खेल के लिए इंडोर गेम्स के रूप में कैरम, सांप-सीढ़ी, लुडो आदि उपलब्ध हैं तथा बाल गृह में चिकित्सक द्वारा नियमित रूप से भ्रमण कर बालकों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। इसके साथ ही इंटरनिश

प्रक्षेत्र दिवस मनाया

जालोर, (कासं)। कृषि विज्ञान केंद्र केशवना जालोर के तत्वावधान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन लिलह योजना के तहत विराणा ग्राम में सरसों की फसल पर प्रक्षेत्र दिवस का आयोजन किया गया। केन्द्र के शस्य वैज्ञानिक बिरम सिंह गुर्जर ने बताया कि केंद्र द्वारा विराणा ग्राम में कुल 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए 25 कृषको के यह प्रदर्शन लगाए गए। उन्होंने बताया कि सरसों की उन्नत किस्म बृजराज जिसकी औसत उपज 17-18 किंक्टल प्रति हेक्टेयर है तथा यह किस्म 130-132 दिनों में पककर तैयार हो जाति है। इस प्रदर्शन में बीज उपचार ट्राईकोटोन के किया गया। यह किस्म अंडी पैदावार और तेल की मात्रा के लिए किसानों में काफी लोकप्रिय है साथ ही इसके पोषे मजबूत और फलियों का विकास अच्छा हुआ है। कार्यक्रम का संचालन केंद्र की प्रसार विशेषज्ञ सुमन शर्मा ने किया। प्रक्षेत्र दिवस पर कुल 35 षकों ने भाग लिया।

पांचोटा के ग्रामीणों ने रोष जताया



ग्राम पंचायत पांचोटा के ग्रामीण जिला कलेक्टर जालोर को ज्ञापन देने पहुंचे। फोटो-राष्ट्रदूत

जालोर/आहोर, (का.सं.)। आहोर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पांचोटा के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर जालोर को ज्ञापन दिया। बताया कि हमारे ग्राम पंचायत में वार्ड के लोगो को इधर से उधर जोड़ दिया है। एक ही परिवार के मतदाता को अलग अलग वार्डों में जोड़ा गया है, कही लोगो के तो गांव बदल गये जी नवीन वार्ड गठन किया है वो समस्त

निरस्त किया जाये और पुनः पुराने वार्ड वयवस्था है उनकी सीमा घटाई जाये। वार्ड के लिए एक कमेटी का गठन कराकर जांच की जाये और नवीन वार्ड बनाये जाये। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों के नाम ही दूसरे वार्ड में जोड़े है, जिससे आने वाले पंचायत चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा।ग्राम पंचायत में मैं सबसे अधिक नोटिस भी अनुसूचित जन जाति के

जीरावल चौराहे पर कटारिया का स्वागत

रेवदर, (नि.सं)।सिरोही जिलें में रेवदर के जीरावल चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया का स्वागत किया।

राज्यपाल का कार्यकर्ताओं द्वारा जीरावल चौराहे पर सौमैया कर किया

उनका अभिनंदन भाजपा प्रदेश मंत्री नारायण पुरोहित एवं पूर्व विधायक जगसीराम कोली के नेतृत्व में स्वागत किया। जिला प्रमुख अर्जुनराम पुरोहित ने राज्यपाल का पारंपरिक रूप से तलवार भेंट की। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को दुपट्टा व

लोगो को ही दिए गये है जिससे, मतदाता सूची से नाम हटने का भी कारण हो सकता है। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि सुरताराम मीणा पांचोटा, उपसरपंच रूपाराम मीणा, प्रवीण कुमार, हिमताराम, बाबू लाल मीणा मनाराम, भंवरलाला हकमारा म पेकाराम रताराम आधारम बालाराम, पालाराम पदमाराम, महेन्द्र, इंदराम, व समस्त पांचोटा के ग्रामीण मौजूद रहे।

ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी लोडिंग टैक्सी कार से भिड़ी

जोधपुर, (कासं) । बोरानाडा कंटेनर डिपो के सामने एक गंभीर सड़क दुर्घटना हो गई। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर ले जा रही लोडिंग टैक्सी और गलत दिशा से आ रही किया कार की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों गाड़ी क्षिततास्त हो गई। वहीं टैक्सी चालक घायल हो गया।

हादसा उस समय हुआ जब टैक्सी बोरानाडा इंडस्ट्रियल एरिया की ओर जा रही थी। टक्कर इतनी तेज थी कि किया कार के एयरबैग खुल गए, जिससे कार चालक को कोई गंभीर चोट नहीं आई और वह सुरक्षित रहा। वहीं लोडिंग टैक्सी चालक हैडल और टैक्सी के बीच बुरी तरह फंस गया।

टक्कर के बाद टैक्सी का अगला हिस्सा झुक गया, जिससे चालक को बाहर निकालना मुश्किल हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए करीब 15 से 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद टैक्सी का हैडल तोड़कर चालक को बाहर निकाला। हादसे में टैक्सी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर बोरनाडा पुलिस मौके पर पहुंची।

टक्कर के बाद टैक्सी का अगला हिस्सा झुक गया, जिससे चालक को बाहर निकालना मुश्किल हो गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए करीब 15 से 20 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद टैक्सी का हैडल तोड़कर चालक को बाहर निकाला। हादसे में टैक्सी चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलने पर बोरनाडा पुलिस मौके पर पहुंची।

युवक ने नीम पर लगाया फंदा

जोधपुर, (कासं) । गगाड़ी ताजनगर में एक युवक ने नीम के पेड़ पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या का कारण पता नहीं चला है।

मथानिया पुलिस ने बताया कि ताजनगर गगाड़ी मथानिया निवासी 30 वर्षीय मनोहर सिंह पुत्र भंवरसिंह अपने घर से निकला था। मगर वह वापिस घर नहीं पहुंचा। इस पर उसकी तलाश की गई तो वह एक नीम के पेड़ पर फंदा लटकाए मिला। उसे फंदे से उतारा गया मगर उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस को सूचना दिए जाने पर वहां पहुंची। रिस्तेदार ताज नगर गगाड़ी निवासी खींवसिंह पुत्र भीखसिंह ने रिपोर्ट दी है।

ग्राम उत्थान शिविर लगाए

जालोर, (कासं)। राज्य सरकार के निर्देशानुसार गुरूवार को जिले में निर्धारित कार्यक्रमानुसार 8 गिरदावर वृत्त पर एक दिवसीय ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन किया गया।

जालोर जिले में गुरूवार को बाकरा रोड़, चान्दराई, रामा, मंगलवा, माण्डोली, चित्तरोड़ी, सरनाऊ व केरिया गिरदावर सर्किल पर एक दिवसीय ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें लाभान्वित किया गया। शिविरों में कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, जल संसाधन, ऊर्जा, उद्योग, आपदा प्रबंधन, ग्रामीण एवं पंचायतीराज विभाग सहित संबंधित विभागों की सहभागिता से कृषकों एवं पशुपालकों सहित ग्रामीणों को विभागीय योजना की जानकारी उपलब्ध कराकर लाभ प्रदान किया गया। जालोर जिले में

6 फरवरी को बागरा, दांतलावास, जाखड़ी, गोलासन व हाडेवा गिरदावर सर्किल पर ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन कर ग्रामीणों को विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उन्हें लाभान्वित किया जायेगा। राज्य सरकार के निर्देशानुसार मंगलवा गिरदावर सर्किल पर आयोजित ग्राम उत्थान शिविर में मंगलवा ग्राम निवासी लाभार्थी कृषक मेहराराम पुत्र हंजाराम मेघवाल ने बताया कि कृषि विभाग की योजना के तहत खेत तलाई पर उसे 1 लाख 5 हजार रूपये का अनुदान मिला। जिससे अब परम्परागत खेती के साथ-साथ आधुनिक कृषि यंत्रों को अपनाकर उन्होंने न केवल अपनी आय बढ़ाई

बल्कि खेतों में होने वाले कृषि अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन का उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत किया।
प्रगतिशील कृषक आयोजन कर ग्रामीणों ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा संचालित अनुदान योजनाओं के अंतर्गत स्टू रीपर मशीन क्रय किया जिस पर उन्हें योजना के तहत 1 लाख 5 हजार रूपये की राशि का अनुदान मिला। इस यंत्र की सहायता से उन्होंने फसलों की कटाई एवं बाद खेतों में बचे भूसे, डंडल एक अन्य अवशेषों को एकत्र कर चारा के रूप में तैयार कर स्थानीय गौशाला में बेचा, जिसमें अपशिष्ट को जलाने की आवश्यकता समाप्त हो गई और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिला। उन्होंने बताया कि इस आधुनिक यंत्र के प्रयोग से उन्होंने एक वर्ष के भीतर लगभग 2 लाख रूपये की अतिरिक्त आय अर्जित की है साथ ही करीब 100 टॉली कृषि अपशिष्ट का सफलतापूर्वक प्रबंधन करे।

मुख्यमंत्री ने दो वर्ष की उपलब्धियों के दस्तावेज सदन पटल पर रखे

राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए भजनलाल ने कहा, दो वर्ष में राजस्व घाटा 8000 करोड़ कम किया

जयपुर, 5 फरवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुईं बहस का जवाब देते हुए पहली बार दो वर्ष की उपलब्धियों का दस्तावेज सदन के पटल पर रखा। उन्होंने अपने वक्तव्य में सड़क, बिजली, पानी, कृषि, महिला, युवा कल्याण सहित विभिन्न

■ **“खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष, इसे बचाने के लिये कानून लायेंगे।”**

■ **“देश की 11 जनकल्याणकारी योजनाओं में राजस्थान पहले स्थान पर है।”**

■ **“वर्ष 2023 की तुलना में 2025 में 14.13 प्रतिशत अपराध में कमी आई।”**

क्षेत्रों में वर्तमान सरकार द्वारा दो साल में किए गए कार्यों का तुलनात्मक ब्यूरा सदन के सामने रखा और कहा कि राज्य सरकार ने अर्थव्यवस्था को न केवल स्थिरता दी, बल्कि उसे गति और दिशा भी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष भी है, राजस्थान की पहचान भी है, जिसकी बढ ते हुए रेगिस्तान को रोकने में हमेशा सार्थक



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुईं बहस का जवाब दिया।

भूमिका रही है। शर्मा ने कहा कि हम राज्य के कल्पवृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए कानून भी लाएंगे, जिससे प्रदेश में खेजड़ी संरक्षित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने वृक्षारोपण का महाअभियान चलाया और केवल दो वर्षों में 2० करोड़ पौधे लगाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो सालों के कार्यकाल में हमारा प्रदेश 11 जनकल्याणकारी योजनाओं में देश में प्रथम स्थान पर रहा है। इसी प्रकार 5 राष्ट्रीय योजनाओं में दूसरे स्थान पर और 9 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में तीसरे स्थान के

साथ ही दो प्रमुख आयामों में बेस्ट परफॉर्मर स्टेट का सम्मान हासिल किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र को समृद्ध और किसानों को खुशहाल बनाने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। हम पांच साल के भीतर किसान सम्मान निधि को दोगुना करेंगे। दो साल के भीतर ही हम इसे डेढ़ गुना कर चुके हैं।

शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कठोर कदमों से वित्त 2 वर्षों से अपराध के ग्राफ में निरन्तर कमी आई है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2023 की तुलना में वर्ष 2025 में

ईसाई रीति से हुए ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिणु अदालत ने कहा कि विवाह केवल रिश्ते संबंध नहीं, बल्कि एक वैधानिक स्थिति है। जिससे उत्तराधिकार, सामाजिक सुरक्षा और भरण पोषण सहित अन्य परिणाम उत्पन्न होते हैं।

जनहित याचिका में अधिवक्ता सुसेन मैथ्यू ने अदालत को बताया कि प्रदेश में ईसाई युगल ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 के तहत विवाह करते हैं। इस अधिनियम के तहत विवाह कराने वाले पादरी की ओर से जो विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसे ही पंजीकृत किया जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद इन विवाहों को नगर

राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अनिवार्य विवाह पंजीकरण अधिनियम के प्रावधान ईसाई विवाहों पर लागू नहीं होता है।

इण्डो-यूएस ट्रेड ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भारतीय उत्पादों पर 18 प्रतिशत या उससे ज्यादा शुल्क लगाया जाए। अमेरिकी दावों की किसी आधिकारिक ख़ोत से पुष्टि नहीं हुई है। रूसी तेल की भारत द्वारा ख़रीद के मुद्दे पर आधिकारिक जानकारी सिर्फ़ इतनी है कि भारत वेनेजुएला के कच्चे तेल के आयात की संभावना पर विचार करने को तैयार है। अगर वेनेजुएला का तेल रूसी तेल से सस्ता होगा, तो भारत के लिए बाढ़ से तेल ख़रीदना फायदेमंद हो सकता है।

रूस से तेल ख़रीदने का मुख्य कारण कम कीमत थी। रूस भारी छूट देकर तेल बेच रहा था क्योंकि दूसरी जगहों पर उसकी बिक्री कम हो रही थी। रूस से तेल ख़रीदने से भारत का तेल आयात खर्च काफी कम हुआ था। रूस से तेल ख़रीद पूरी तरह बंद होने के करीब नहीं है। अगर इसमें कोई बड़ी कमी आती भी है, तो उसे लागू होने में कई साल लग सकते हैं। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर भारत और अमेरिकी राष्ट्रपति, दोनों को कुछ न कुछ फायदा मिलता दिख रहा है।

याचिका में कहा गया है कि इस अवधि में नकद लाभ जारी करना “भ्रष्ट आचरण” था, जो मतदाताओं को अनुचित तरीके से सत्तारूढ़ सरकार के पक्ष में प्रभावित करने के लिए था।

बिहार चुनाव में “कैश ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
के लिए पात्रता को (महिला स्वयं सहायता समूहों के नेटवर्क) की सदस्यता से जोड़ा गया था। राज्य ने घोषणा की थी कि पहले से जीविका योजना का हिस्सा न होने वाली महिलाएँ भी इस योजना में नामांकन कर लाभ उठा सकती हैं।

जन सुराज पार्टी ने आरोप लगाया है कि जब आचार संहिता लागू हुई तब लगभग एक करोड़ महिलाएं पहले से जीविका से जुड़ी हुई थीं, बाद में समाचार पत्रों की रिपोर्टों में यह सामने आया कि कुल 1.56 करोड़ महिलाओं को भुगतान किया गया।

याचिका का दावा है कि यह दर्शाता है कि नए लाभार्थियों को चुनावी कार्यक्रम की घोषणा के बाद जोड़ा गया और भुगतान किया गया, जबकि चुनाव आचार संहिता लागू थी।

याचिका में कहा गया है कि इस अवधि में नकद लाभ जारी करना “भ्रष्ट आचरण” था, जो मतदाताओं को अनुचित तरीके से सत्तारूढ़ सरकार के पक्ष में प्रभावित करने के लिए था। याचिका का यह भी दावा है कि इससे अन्य राजनीतिक दलों को समान अवसर नहीं मिला और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की मौलिक आवश्यकता पर आक्रमण था।

याचिका में चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि जो इस

संसद में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
प्रधानमंत्री के जवाब के 3समय की प्रतिक्रिया के बारे में विशेष चर्चा हुई।

बैठक में खड़गे के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, राज्यसभा में द्रमुक के तिरुवि एम. शिवा, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल वर्मा, शिव सेना उद्भव गुट के अरविंद सावंत, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ईटी बशीर अहमद सहित विभिन्न दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया।

बाद में कांग्रेस संसदीय दल के नेताओं की भी पार्टी के सांसद दल के कार्यालय में बैठक हुई जिसमें गांधी सहित पार्टी के कई नेताओं ने हिस्सा लिया।

प.बंगाल ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांग्रेस को एकतरफा समर्थन देना चाहिए। प्रदेश के एक कांग्रेस नेता ने कहा, “यह ठीक है कि आप अपने घर में मजबूत हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों को कुचल डालें।”

“अकेले चलने के फैसले पर हरी झंडी मिलने की पुष्टि करते हुए, पश्चिम बंगाल से कांग्रेस के एकमात्र सांसद इशा खान चौधरी ने कहा कि इस फैसले को राहुल गांधी का आशीर्वाद प्राप्त है। कांग्रेस बंगाल के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने भी इस फैसले की पुष्टि की।

‘दुनिया का सबसे अमीर देश भी घुसपैठियों को निकाल रहा है’

प्रमंत्री मोदी ने तृणमूल पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल घुसपैठियों की वकील बन सुप्रीम कोर्ट तक आ गई है

नयी दिल्ली, 05 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग की मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम और सरकार के आर्थिक सुधारों सहित विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के विरोध पर गुरुवार को राज्य सभा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सोच और राजनीति पर तीखे हमले किये।

मोदी ने विपक्ष के बहिष्कार के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन में चर्चा का जवाब देते हुए एसआईआर के विरोध के लिए तृणमूल कांग्रेस की आलोचना करते हुए तृणमूल के लोगों को अपने गिरिबां में झांकने की सलाह दी और कहा कि तृणमूल पतन के नये मानदंड बना रही है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार को निर्मम सरकार बताते हुए कहा कि वह लोगों को भविष्य अंधकार में डाल रही है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का सबसे समृद्ध देश भी अपने यहां से गैर कानूनी नागरिकों को निकाल रहा है, लेकिन तृणमूल के लोग घुसपैठियों की

अल-फलाह चेयरमैन सिद्दीकी चार दिन पुलिस हिरासत में

नयी दिल्ली, 05 फरवरी। एक निचली अदालत ने विवादों में घिरे अल-फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को कथित धोखाधड़ी और वित्तीय कदाचार के मामले में चार दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है।

सिद्दीकी को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे आगे की पुछताछ के लिए चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। यह कार्रवाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा दर्ज कराई गई औपचारिक शिकायतों के बाद शुरू की गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा (क्राइम ब्रांच) ने उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, अपराध शाखा ने यूजीसी की शिकायतों के आधार पर सिद्दीकी के खिलाफ दो अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की थीं।

‘सदन में प्रमंत्री के साथ हादसा हो सकता था, मैंने उन्हें सदन में आने के लिए मना किया था’

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया बेहद गंभीर चौंकाने वाला खुलासा

नई दिल्ली, 05 फरवरी। संसद के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ है जब लोकसभा अध्यक्ष ने खुद यह स्वीकार किया है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सम्मान को सदन के भीतर ही खतरा था।

लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने गुरुवार को एक बेहद गंभीर और चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने ही कल (बुधवार) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आने से रोका था। बिड़ला ने आशंका जताई

मेघालय में अवैध कोयला खदान में धमाका, 1 8 मजदूरों की मौत

खदान में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है

■ **प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर गहरा दु:ख जताया, मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रु. व घायलों को 50,000 रु. देने की घोषणा की।**

ने मोदी के हवाले से एक पोस्टर में कहा, “मेघालय के पूर्वी जयंतिया हिल्स में हुई दुर्घटना से व्यथित हूं। अपनों को खोने वालों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।” मोदी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख

रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जबकि घायलों को 50,0०0 रुपये दिए जाएंगे।

आधिकारिक रूप से मिली जानकारी के अनुसारमेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में गुरुवार को “अवैध कोयला खदान में विस्फोट होने से कम से कम 16 मजदूरों की मौत हो गई और कई अन्य के फंसे होने की आशंका है। पुलिस महानिदेशक आई नोंगरंग ने यह जानकारी दी। डीजीपी ने बताया कि यह घटना थांगस्कु इलाके में हुई और बचाव दल तलाशी अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा, “हमने अब तक 16 शव बरामद किए हैं, लेकिन विस्फोट के समय खदान के अंदर मौजूद लोगों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। कई लोगों के फंसे होने की आशंका है।

‘सदन में प्रमंत्री के साथ हादसा हो सकता था, मैंने उन्हें सदन में आने के लिए मना किया था’

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने किया बेहद गंभीर चौंकाने वाला खुलासा

■ **ओम बिड़ला ने कहा उन्हें खुफिया जानकारी के साथ सदन के भीतर के हालात से इनपुट मिला था कांग्रेस के सांसद प्रमंत्री के कुर्सी के पास आकर हंगामा कर तथा अनहोनी करने की योजना बना रहे हैं।**

कि अगर पीएम मोदी कल सदन में आते, तो उनके साथ कोई अप्रत्याशित और अग्रिय घटना घट सकती थी।

स्पीकर ने बताया कि उन्हें खुफिया जानकारी और सदन के भीतर के हालात से यह इनपुट मिला था कि

आसाराम के अहमदाबाद आश्रम पर बुलडोजर चलेगा

अहमदाबाद, ०5 फरवरी।

आसाराम का अहमदाबाद स्थित आश्रम टूटेगा। गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार को मोटेरा आश्रम ट्रस्ट की तरफ से दायर याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में शहर के मोटेरा इलाके में स्थित भूखंड को खाली कराने की सरकारी कार्रवाई को चुनौती दी गई थी।

कोर्ट के फैसले से राज्य सरकार के लिए आश्रम की जमीन अपने कब्जे में लेने का रास्ता साफ हो गया है। आश्रम की 45,०00 वर्ग मीटर से ज्यादा की जमीन पर 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाेगा। वर्तमान में इस जमीन की मार्केट वैल्यू 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की है।

गुजरात हाईकोर्ट की जस्टिस वैभवजी नानावादी ने इस मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने गुरुवार को अपने आदेश में कहा कि आश्रम में नियमों का उल्लंघन हुआ। उस जगह का विकास परियोजना को जरूरत भी है, इसलिए सरकार की मांग सही है।

इस फैसले के बाद अहमदाबाद नगर निगम कभी भी आश्रम में बने अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर सकता है।

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सीनियर पब्लिक प्रॉसीक्यूटर जीएच विर्क ने कोर्ट को बताया कि यह जमीन

■ **गुजरात हाईकोर्ट ने आश्रम की जमीन लेने की सरकारी कार्यवाही को सही ठहराया**

दशकों पहले सीमित धार्मिक उपयोग के लिए दी गई थी। लेकिन, धीरे-धीरे इसका विस्तार होता चला गया।

जबकि, भूमि आवंटन की शर्तों के अनुसार इसका व्यावसायिक उपयोग, अनधिकृत निर्माण और बिना अनुमति विस्तार प्रतिबंधित था। आश्रम परिसर में करीब 32 अवैध स्ट्रक्चर बना लिए गए, जो कानूनी सीमाओं से बाहर है।

उन्होंने बताया कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (एएमसी) ने आश्रम को कई बार नोटिस भेजे थे। इसके बाद 21 जनवरी 2०26 को नगर निगम ने आश्रम का आवेदन भी खारिज कर दिया था।

साबरमती नदी किनारे इस आश्रम की स्थापना आसाराम ने 1972 में की थी। आसाराम ने यहां सबसे पहले एक कुटिया बनाई थी, जिसे मोक्ष कुटिया के रूप में पहचाना जाता था। धीरे-धीरे इसी कुटिया के आसपास निर्माण कार्य होता चला गया और बाद में इसे आसाराम मोटेरा आश्रम के नाम से पहचाना जाने लगा।

चुनावों में बढ़ते “रेवड़ी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

याचिकाकर्ता ने अदालत से कहा, पांच विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। अब तो सिर्फ सूरज और चांद का वादा करना बाकी रह गया है। ये भ्रष्ट तरीके हैं।

उपाध्यक्ष द्वारा दायर जनहित याचिका में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को चुनावी घोषणापत्र को नियंत्रित करने और सरकारी खर्च से जुड़े वादों के लिए जवाबदेही तय करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में ऐसे वादों के दीर्घकालिक आर्थिक परिणामों और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर पड़ने वाले असर को लेकर भी चिंता जताई गई है।

ज्यादातर राजनीतिक दलों ने इस याचिका का विरोध किया है। कुछ दलों ने इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और कहा कि कल्याणकारी योजनाएं और सब्सिडी शासन का जरूरी हिस्सा हैं और समाज के कमजोर वर्गों को मदद के लिए होती हैं।

स्पीकर मोदी ने पहले की सुनवाई में यह स्वीकार किया है, कि यह मुद्दा जटिल है, क्योंकि यह चुनावी और नीतिगत मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाओं के बारे में कठिन सवाल उठाता है। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि 2०13 में सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार मामले में दिए गए फैसले पर दोबारा विचार करने की जरूरत हो सकती है। उस फैसले में कहा गया था कि चुनावी घोषणापत्र में मुफ्त

^[1] राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मूद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं॰ RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुरा फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स: 0141-2373513, कोटा कार्यालय: पलायका हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा फोन: 2386031, 2386032 फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय: कुम्भारा हाऊस, हनुमान हवा, बीकानेरा फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आनंद मेन रोड आनंद, उदयपुरा फोन: 2413092, फैक्स: 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चूंगी नाका के पास, अजमेरा फोन: 26227612, फैक्स:0145-2624665 जालौर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्टीयल एरिया, फेस प्रथम, जालौरा फोन726422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डीनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डीनसिटी। फोन: 230200, 2304000, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908